उत्तराखण्ड सरकार
मा.मुख्यमंत्री प्रेस सूचना ब्यूरो
(सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग)
मुख्यमंत्री आवास, न्यू कैंट रोड, देहरादून
E-mail : infodirector.uk@gmail.com
Website : www.uttarainformation.gov.in

देहरादून 08 जनवरी, 2018(सू.ब्यूरो) प्रेस नोट–03(01/22)

केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जहाजरानी, जलसंसाधन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नमामि गंगे योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में किये जा रहे कार्यों को 31 दिसम्बर, 2018 तक पूर्ण करने के निर्देश दिये है। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि इस योजना के अन्तर्गत पूर्ण होने वाली योजनाओं के रख–रखाव की जिम्मेदारी भी कार्यदायी संस्था को सौंपी जाए। गंगा यमुना के अतिरिक्त काली गंगा, राम गंगा के साथ ही सहायक नदियों के सीवेज ट्रीटमेंट की भी कार्ययोजना बनायी जाए। केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने देहरादून को भी नमामि गंगे योजना में शामिल करने पर सहमति जतायी है। उन्होंने अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट के बाद गंदा पानी नदियों में न प्रवाहित हो।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, मुख्य सचिव एवं सम्बंधित विभागीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुखों के साथ उत्तराखण्ड में संचालित नमामि गंगे की योजनाओं की सोमवार को आई.एस.बी.टी. के समीप स्थित एक स्थानीय होटल में समीक्षा करते हुए केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि उत्तराखण्ड में संचालित नमामि गंगे के 1191 करोड रूपये के 66 कार्य प्रस्तावित है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन व गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के अधीन सुनिश्चित करने के निर्देश भी केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने दिये।

केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी ने सुझाव दिया कि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट(एस.टी.पी.) के पानी की रिसाइक्लिंग कर उसके व्यवसायिक उपयोग की दिशा में भी पहल की जाए। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के अधीन किये जाने वाले कार्यों के लिये धनराशि की कमी नही होने दी जायेगी। इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा तकनीकि सहयोग भी दिया जायेगा। गंगा की शुद्धता से जुडी योजनाओं के वित्तीय सहयोग पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि रिवरफ्रंट डेवलपमेंट के कार्यों के साथ ही घाटो, मोक्षधाम आदि के निर्माण के लिए सीएसआर के अधीन वित्तीय सहयोग लिया जायेगा, इसके प्रयास किये जा रहे है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केन्द्रीय मंत्री श्री गडकरी को आश्वस्त किया कि नमामि गंगे सहित प्रदेश में केन्द्र के सहयोग से संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन की गति में तेजी लायी जायेगी। योजनाएं निर्धारित समय अवधि में पूर्ण हो, इसके लिये भी प्रभावी प्रयास किये जा रहे है।

इस अवसर पर सचिव श्री अरविंद सिंह ह्यांकी एवं अपर सचिव डॉ.राघव लंगर ने प्रदेश में नमामि गंगे के अन्तर्गत संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रस्तुतिकरण दिया गया।

बैठक में केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री अजय टम्टा, सांसद हरिद्वार डॉ.रमेश पोखरियाल 'निशंक', राज्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग।

देहरादून 08 जनवरी, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–02(01/21)**

केंद्र सरकार ने उत्तराखण्ड के लिए भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 10 हजार करोड़ रूपये की लागत से 570 किलोमीटर लंबाई की कुल 05 सड़कें मंजूर की है। इन सभी सड़कों पर निर्माण कार्य अगले 06 माह में शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। 05 प्रोजेक्ट में, 94 किलोमीटर 2000 करोड़ रूपये की लागत से बैजनाथ–थराली–कर्णप्रयाग मार्ग, 147 किलोमीटर 1200 करोड़ रूपये की लागत से अस्कोट–धारचूला–मालपा–लिपुलेख मार्ग, 216 किलोमीटर 4500 करोड़ रूपये की लागत से बैजनाथ–बागेश्वर–कपकोट–मुनस्यारी–सेराघाट–जौलजीवी मार्ग, 51 किलोमीटर 1000 करोड़ रूपये की लागत से माना–मूसा पानी–माणा पास तथा 63 किलोमीटर 1000 करोड़ रूपये की लागत से जोशीमठ–मलारी मार्ग सम्मिलित है।

यह जानकारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने सोमवार को एक स्थानीय होटल में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ राज्य की सड़क परियोजनाओं की संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान दी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि वह शीघ्र ही सभी जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर भू–अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और वन भूमि हस्तांतरण के बाकी बचे सभी मामलों पर समयबद्ध कार्यवाही करें। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि राज्य सरकार केंद्र सरकार की सभी परियोजनाओं को शीर्ष प्राथमिकता पर ले रही है और प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, समयबद्धता और आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहने की हिदायत दी। ऊर्जा विभाग को शीघ्र लाइनों और खम्भों को शिफ्ट करने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि चारधाम ऑल वेदर रोड के 900 किलोमीटर मार्ग के सापेक्ष 400 किलोमीटर मार्ग के कार्य अवार्ड कर दिए गए हैं। श्री गडकरी ने भू–अधिग्रहण, मुआवजा वितरण और वन भूमि मामलों में राज्य सरकार की तत्परता पर प्रशंसा की। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने मार्च 2018 तक परियोजना के सारे प्रोजेक्ट के टेंडर करने का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान बड़ेथी और नालूपानी के लैंड स्लाइड क्षेत्रों पर भी काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया कि गंगा यमुना घाटी को जोड़ने वाली 1300 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाली 4.5 किलोमीटर लम्बी सिल्क्यारा टनल पर भी शीघ्र काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली–देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए लगभग 90 प्रतिशत कार्य हेतु जून 2018 और सभी कार्य पूरा करने हेतु दिसम्बर 2018 की डेडलाइन कार्यदायी संस्था और कांट्रेक्टर को दी गई। आलवेदर परियोजना में इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स को अनुश्रवण कमेटी की अनुपस्थिति में सीधे वन मंत्रालय को भेजा जाएगा। दिल्ली–शामली–सहारनपुर–देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बनाया जाएगा और अगले 06 माह में इसका कार्य शुरू होने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने कहा कि वर्ष 2019 तक उत्तराखण्ड में कुल 50 हजार करोड़ रूपये के सड़क कार्य दिए जाएंगे, जिसमें से बहुत से कार्य पूर्ण हो जाएंगे और बहुत से कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। सड़क परिवहन के मामले में उत्तराखण्ड 2019 तक एक बदला हुआ राज्य नजर आएगा। आल वेदर रोड के लिए काटे जा रहे पेड़ों पर टिप्पणी करते हुए श्री गड़करी ने बताया की हर एक पेड़ के बदले 10 पेड़ लगाए जाएंगे। सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में सभी परियोजनाओं के ठेकेदार कंपनियों को भी बुलाया गया था। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने अधिकारियों के समक्ष सभी ठेकेदारों की समस्याएं भी सुनी और उन पर यथोचित कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए। ऑल वेदर रोड परियोजना में बीआरओ द्वारा कार्यों में प्रदर्शित की जा रही शिथिलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने उन्हें शीघ्र ही सभी कार्यों की डीपीआर बनाने के निर्देश दिए ।

बैठक में चारधाम ऑल वेदर रोड के सभी प्रोजेक्ट्स पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ ही टनकपुर–पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग–125 की प्रगति की समीक्षा भी की गई। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत काशीपुर–सितारगंज 4 लेन, सितारगंज–टनकपुर 2 लेन, रुद्रपुर–काठगोदाम 4 लेन, नगीना–काशीपुर 4 लेन, मुजफ्फरनगर–हरिद्वार 4 लेन, हरिद्वार–देहरादून 4 लेन, हरिद्वार– नगीना 4 लेन और एनएच–73 के रुड़की–छुटमलपुर तथा एनएच–72ए छुटमलपुर–गणेशपुर मार्ग की समीक्षा भी की गई।

बैठक में केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री अजय टम्टा, सांसद हरिद्वार डॉ.रमेश पोखरियाल 'निशंक', राज्य मंत्री डॉ.धन सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने बताया कि औली को दावोस की भांति अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन बनाने के लिए काम शुरु किया गया है। इसके लिए विश्व स्तरीय कंसल्टेंसी एजेंसी की सेवा भी ली गई है। कंसल्टेंसी एजेंसी द्वारा उत्तराखण्ड और हिमाचल में ऐसे 100 स्थल चिन्हित किए गए हैं, जहां पर रोपवे ,केबल कार और फरनकुलर रेलवे जैसे वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर इन सभी स्थानों पर विस्तृत चर्चा करेंगे और शीघ्र ही एक ठोस कार्ययोजना बनाई जाएगी। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि उत्तराखंड की बड़ी झीलों और नदियों के लिए सी–प्लेन पर भी विचार किया जा सकता है। यह परिवहन के एक वैकल्पिक साधन के साथ ही पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख जरिया भी बनेगा।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग।

देहरादून 08 जनवरी, 2018(सू.ब्यूरो) **प्रेस नोट–01(01/20)**

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को आईएसबीटी देहरादून स्थित स्थानीय होटल में एक दैनिक समाचार पत्र (अमर उजाला) द्वारा आयोजित ''संवाद उत्तराखण्ड उदय'' कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

गुड गवर्नेंस के साथ जनभावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार चला रहे हैं – सीएम

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पिछले 10 माह में राज्य सरकार ने जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया जा रहा है। राज्य में पारदर्शी स्थानान्तरण अधिनियम लाया गया है। इस अधिनियम से ट्रांसफर और पोस्टिंग के धंधे पर पूरी तरह लगाम लगेगी। आने वाले समय में इसके बहुआयामी प्रभाव दिखेंगे।

सरकारी योजनाओं में तेजी लाने और विभिन्न विभागों के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए सीएम डैशबोर्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड से सरकार के कार्यो में पारदर्शिता व गतिशीलता आयेगी एवं विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। फाइलों का निर्धारित समयावधि में निपटारा न होने पर रेड सिग्नल से जानकारी मिल जायेगी। सीएम डैशबोर्ड से सभी विभागों की योजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग की जा रही है एवं बजट के आउटकम पर नजर रखी जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि एमडीडीए में नक्शे पास कराने के लिए ऑनलाईन की व्यवस्था लागू की गई है। गुड गवर्नेंस के लिए समाधान पोर्टल को मजबूत किया गया है। सेवा के अधिकार के तहत 162 सेवाएं जोड़ी गई हैं। जन शिकायतों के लिए टोल फ्री नम्बर 1905 दिया गया है, जिस पर सम्बन्धित विभाग को शिकायत के 10 दिन के अन्दर शिकायत का जवाब देना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि एन.एच.–74 पर भूमि के मुआवजे को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया जिस पर अभी जाँच चल रही है। प्रारम्भिक जॉच में 02 तहसीलों में 185 करोड़ का घोटाला सामने आया। इस घोटाले में अभी तक 12 दोषियों को जेल भेजा जा चुका है। खाद्यान घोटाले की जाँच चल रही है। खाद्यान घोटाले में तत्कालीन आरएफसी को बर्खास्त किया गया। सुगर मिलों में किसानों को फर्जी रवन्ने देने पर 02 दोषियों को जेल भेजा जा चुका है। पारदर्शी कार्यों के लिए ठेकेदारों के लिए ई–टेंडरिंग व्यवस्था लागू की गई है।

किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने के लिए सरकार कृत संकल्प– सीएम

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए राज्य में पं. दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना चलाई गई है। इस योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को मात्र 02 प्रतिशत की ब्याज दर पर एक लाख रूपये तक का लोन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत अभी तक 01 लाख किसान ऋण ले चुके हैं। अच्छे परिणाम मिलने पर इसकी सीमा को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में चकबन्दी की शुरूवात की जा रही है। इसकी शुरूवात स्वयं मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री के गांव एवं यूपी के मुख्यमंत्री के पैतृक गांव से शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को खाद पर सब्सिडी (डीबीटी) देने वाला उत्तराखण्ड देश का चौथा राज्य है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए चम्पावत के नडियाल गांव में बद्री गाय की नस्ल का सवंर्द्धन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गायों की संख्या में वृद्धि करने के लिए ऋषिकेश में एक सेक्स सीमेन सेंटर बनाये जाने की योजना है। लगभग 48 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले इस सेंटर को अगले एक वर्ष में चालू किये जाने की योजना है।

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध–सीएम

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए औली को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में इन्टरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा हेल्थ इन टूरिज्म के लिए एम्स का दायरा बढ़ाए जाने की योजना है, इसके अलावा होम–स्टे और वैलनेस टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पलायन को रोकने के लिए 670 न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है। इससे न्याय पंचायतों में युवाओं एवं महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसकी शुरूवात 15 न्याय पंचायतों में रेडिमेट गारमेंट के कार्य से शुरू किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों एवं आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स को विद्युत से सम्बन्धित 45 उपकरण बनाने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रयोग के तौर पर इसकी शुरूआत देहरादून के थानो एवं नैनीताल के कोटबाग में की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 14 जनवरी से देहरादून में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलॉजी (सीपैट) की कक्षाएं शुरू की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में छात्र–शिक्षकों के सही अनुपात के लिए स्कूलों की क्लबिंग की जा रही है। क्लबिंग करने के बाद स्कूल में छात्रों को स्कूल जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था करने की योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रिस्पना एवं कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि रिस्पना को जनसहयोग से पुनर्जीवित किया जायेगा। रिस्पना नदी में वृक्षारोपण, नदी की सफाई एवं ट्रेंचेज का पूरा कार्य एक दिन में किया जायेगा। नैनीताल झील के संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण के लिए 03 करोड़ रूपये का फंड आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा देहरादून को पूर्ण ग्रेविटी का पेयजल उपलब्ध कराने की योजना तैयार की जा रही है। इस योजना को साकार करने के लिए सूर्यधार झील का शिलान्यास किया जा चुका है। शीघ्र ही सौंग बांध का भी शिलान्यास किया जायेगा। हल्द्वानी में जमरानी बांध के लिए शीघ्र एमओयू किया जायेगा।

कार्यक्रम के दौरान सिमरन कपूर द्वारा पूछे गये सवाल के जबाब में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देहरादून में पर्यावरण की शुद्धता की दृष्टि से इलैक्ट्रिक वाहनों की शुरूवात करने जा रहे हैं। देहरादून को सीएनजी से जोड़ने की योजना है। पेट्रोल एवं डीजल गाड़ियों को धीरे–धीरे सीएनजी में बदलने का प्रयास किया जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदूषण को रोकने के लिए विक्रमों के नये परमिट को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। सुमेधा द्वारा पूछे गये प्रश्न के जबाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने एवं उत्तराखण्ड की संस्कृति की झलक एक ही स्थान पर मिले इसके लिए सरकार द्वारा ''संस्कृति ग्राम'' बनाने की योजना है।

इस अवसर पर महिला बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्य, प्रदेश महामंत्री श्री नरेश बंसल, महानगर अध्यक्ष श्री विनय गोयल, सूचना महानिदेशक डॉ.पंकज पाण्डेय आदि उपस्थित थे।

सूचना एवं लोक संपर्क विभाग।